भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2109

उत्तर देने की तारीख 18 दिसंबर, 2025 (गुरूवार)

27 अग्रहायण, 1947 (शक)

प्रश्न

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में परियोजनाओं की निगरानी

2109. श्री कणाद पुरकायस्थः

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में परियोजना निगरानी प्रणालियों को सुदृढ़ करने में क्या नवीनतम प्रगति हुई है, जिसमें पिछले वर्ष के दौरान निरीक्षण की गई और कार्यान्वित की गई परियोजनाओं की संख्या और प्रतिशत शामिल है;

(ख) पूर्वोत्तर विकास सेतु जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग और इन सुधारों के मापनीय परिणाम सहित इन परियोजनाओं की वास्तविक समय निगरानी में सुधार के लिए किए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले वर्ष के दौरान मंत्रालय की समीक्षा प्रणाली के अंतर्गत पहचानी गई विलंबित या रुकी हुई परियोजनाओं की संख्या कितनी है और ऐसी परियोजनाओं के बंद करने, धन वापसी या इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने सभी 08 पूर्वोत्तर राज्यों में फील्ड स्तरीय तकनीकी सहायता इकाई (एफटीएसयू) स्थापित करके निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। ये एफटीएसयू परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ नियमित रूप से बातचीत करते हैं और पीएम गति शक्ति पोर्टल पर परियोजनाओं का डेटाबेस अनुरक्षित करते हैं और उसे अपडेट करते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के निगरानी तंत्र को और मजबूत करने के लिए परियोजना गुणवत्ता मॉनिटर (पीक्यूएम)/तृतीय पक्ष तकनीकी निरीक्षण (टीपीटीआईए) एजेंसियां शुरू की गई हैं। इसके अलावा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) के अधिकारियों द्वारा परियोजनाओं की समय-समय पर निगरानी और जांच की जाती है। 2024-25 के दौरान कुल 599 परियोजनाओं का निरीक्षण किया गया और 2025-26 के दौरान (12.12.2025 तक) 198 परियोजनाओं का निरीक्षण किया गया है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने पीएम गति शक्ति पोर्टल के साथ एकीकरण के माध्यम से परियोजनाओं की रियल टाइम निगरानी में काफी सुधार करने के लिए कई सुधार किए हैं। नए प्रस्ताव अपलोड करने तथा टिप्पणियों/समर्थन के लिए संबंधित मंत्रालयों/नीति आयोग को प्रस्ताव भेजने और मांग प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए पूर्वोत्तर विकास सेतु (पीवीएस) पोर्टल चालू किया गया है। इसके अलावा, पीवीएस पोर्टल के माध्यम से परियोजनाओं की निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती हैं, जिससे परियोजनाओं की रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग और निगरानी संभव हो पाती है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय पुरानी विलंबित परियोजनाओं सहित सभी परियोजनाओं के निष्पादन में तेजी लाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें करता है। जो परियोजनाएं बहुत ज़्यादा विलंबित थीं या लंबे समय से रुकी हुई थीं, उन्हें पूर्वोत्तर राज्यों के साथ उचित परामर्श के बाद 'जैसा है वैसा ही' आधार पर या 'पूरा रिफंड' आधार पर समय से पहले बंद (फोरक्लोज) कर दिया गया है। 12.12.2025 तक, कुल 48 परियोजनाओं को समय से पहले बंद कर दिया गया है, जिनमें से 17 परियोजनाएं 'जैसा है वैसा ही' आधार पर और 31 परियोजनाएं 'पूरा रिफंड' आधार पर समय से पहले बंद की गई हैं।

*****